

कृषिव्यापार में सुगमता की जाँच के लिये नया सूचकांक (New index to check ease of doing agri-business)

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार अगले वर्ष की शुरुआत में कृषिव्यापार में सुगमता हेतु एक नया सूचकांक शुरू करना चाहती है। यह सूचकांक राज्यों को कृषि में उनके नविश, उत्पादकता में वृद्धि, इनपुट लागत में कमी और जोखिम शमन उपायों के साथ ही साथ अन्य सुधारों के आधार पर रैंक प्रदान करेगा।

प्रमुख बंदि

- राज्यों को जल्द ही कृषिव्यापार को प्रोत्साहित करने में विशेषकर वपिणन, भूमि और शासन में सुधारों के संबंध में उनके प्रदर्शन के आधार पर कृषि मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिये अतिरिक्त धनराशि मिलने की शुरुआत हो सकती है।
- सूचकांक के लिये जारी किये गए हालिया अवधारणा नोट में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय विभिन्न प्रमुख योजनाओं में उपलब्ध फ्लेक्सि फंडों से आवंटन के साथ प्रदर्शन को जोड़कर उच्च नषिपादति राज्यों को [पूरण और वृद्धिशील दोनों शर्तों में] पुरस्कृत करने पर वचिार कर सकता है।
- नीतिआयोग पहले से ही एक कृषि वपिणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है, जो इन सुधारों के कार्यान्वयन पर राज्यों को रेटिंग प्रदान करता है। वर्ष 2016 में उस सूचकांक के प्रारंभिक संस्करण में महाराष्ट्र रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा, इसके बाद गुजरात का स्थान था।
- इस प्रस्तावति सूचकांक का वसितार अत्यंत व्यापक है, लेकिन मुख्य केंद्रण अभी भी सुधारों पर है। वपिणन सुधार (25%) तथा शासन और भूमि सुधार (20%) इस सूचकांक की मूल्यांकन प्रणाली के मापदंडों के वजन का लगभग आधा हसिसा रखते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- अन्य मापदंडों के तहत, राज्यों का मूल्यांकन मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वतिरण तथा जैवकि कृषि और सूक्ष्म सचिाई को प्रोत्साहित करके कृषि आगतों (20% भारांश) की लागत में कमी करने में राज्यों को मल्लि सफलता के आधार पर कथिा जाएगा।
- फसल और पशुधन बीमा जैसे जोखिम शमन उपायों का भारांश 15% होगा, जबकि कृषि में उत्पादकता तथा नविश में वृद्धि इन दोनों का भारांश 10-10% होगा।

प्रक्रथिा उनमुख मापदंड

- अवधारणा नोट के अनुसार, ये मापदंड प्रक्रथिा उनमुख हैं, और जब नए सुधार या पहल प्रस्तावति कथिा जाते हैं, तब ये वकिसति होते हैं।
- चूँकि कृषि एक राज्य वषिय है, अतः केंद्र द्वारा प्रस्तावति नीतथियों और सुधार पहलों की सफलता राज्यों द्वारा कार्यान्वयन पर नरिभर है।
- इस नोट के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकार के सुधार एजेंडे को सभी राज्य सरकारों द्वारा वांछति गति से लागू कथिा गया है, राज्यों के बीच एक प्रतसिपर्द्धी भावना वकिसति करने की आवश्यकता है।
- 2022 तक कसिानों की आय को दोगुना करने की रणनीतथियों की सफिराश करने के लिये गठति समतिि ने भी यह सुझाव दथिा था कि राज्यों को उनके सुधार और शासन रकिॉर्ड के आधार पर रैंक प्रदान कथिा जाना चाहथिे।
- यह अवधारणा नोट 15 नवंबर तक सार्वजनकि और हतिधारकों की प्रतकि्रथिा के लिये उपलब्ध है, जसिके बाद महीने के अंत तक कार्यान्वयन दशानरिदेश तैयार कथिा जाएंगे।
- अवधारणा नोट की समय-सारणी के अनुसार, राज्य के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड वर्ष के अंत तक वकिसति कथिा जाएगा और सूचकांक को जारी करने के लिये राष्ट्रीय स्तर की कारथशाला जनवरी 2019 में आयोजति की जाएगी।